Report of working group on Tribal development

9263. SHRIMATI PARVATI DEVI: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the working group on tribal development had proposed specific allotment for the welfare of tribals during the Sixth Five Year Plan period; and

(b) if so, the details thereof and the list of items to be undertaken thereunder?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) Yes, Sir.

(b) The Working Group has recommended a minimum order of investment of Rs. 3000 crores in the period 1978—83 on tribal welfare: about Rs. 1850 crores from State Plans, Rs. 500 crores from Central Ministries' Plans, Rs. 300 crores from the institutional finance and Rs. 350 crores as special Central assistance. The tribal sub-plans of the States, and outlays on the programmes of Central Ministries which will benefit tribal population are still under consideration.

Protest March against atrocities on Adivasis in Katihar District of Bihar

9264. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the protest march of Adivasis and Harijans at Patna on the 21st March, 1979 against the atrocities on Adivasis in Katihar District of Bihar; if so, the facts in details; and

(b) whether these atrocities were also referred to the Central Government for its intervention; if so, the steps taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) Yes, Sir. As per report received from the State Government, an armed rally of Adivasis organised under the joint auspices of Uttranchal Adivasi Harijan Sangharsh Samiti Katihar and Marxist Co-ordination Committee was taken out on 21-3-1979 from Gandhi Maidan for ventilating their grievances against alleged atrocities on Adivasis. The procession marched through main streets and finally demonstrated peacefully before Vidhan Sabha. The processionists returned to Gandhi Maidan after submitting a memorandum to the Agriculture Minister of Bihar.

(b) No, Sir.

हीरा मिल्स और इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स के पास खाली पड़ी जमीन

9265. श्री हुकम चन्द कछवाय क्या उद्योग मंत्री हीरा मिल्स और इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स के पास खाली पड़ी जमीन के बारे में 16 अगस्त, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीरा मिल्स और इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स इंदौर के पास इस समय कितने एकड़ जमीन खाली पड़ी है और कितनी जमीन अन्य व्यक्तियों को किराये पर दी गई है और उस से कितना किराया मिला है और कितना बकाया किराया अभी लिया जाना है ;

(ख) क्या उक्त मिलों के पास नगर के अन्य स्थानों में भी कुछ जमीन है और यदि हां, तो क्या मिलों को अपने नियंत्रणाधीन लिए जाने के समय मिल मालिकों ने उस जमीन को बेच दिया था अथवा गिरवी रख दी थी और यदि हां, तो वह जमीन कितनी है तथा क्या सरकार उस को भी अधिगृहीत करेगी ; और

(ग) क्या उक्त मिलों के नियंत्रणाधीन चल रहे अन्य कारखानों को भी अपने अधीन ले लिया गया है और यदि हां, तो उनके पास कितनी जमीन थी तथा क्या यह भी सच है कि कुछ राजनीतिक दलों ने बलात उस जमीन पर कब्जा जमा लिया है और यदि हां, तो ऐसी जमीन कितनी है तथा यह किन व्यक्तियों के कब्जे में है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) इस समय हीरा मिल्स तथा इंदौर मालवा यूनाइटिड मिल्स के पास क्रमश 57 06 एकड़ तथा 32 12 एकड़ खाली भूमि पड़ी हुई है । इन मिलों का कोई भूमि किराये पर नही दी गई है अत एव किराये की राशि का प्रश्न ही नही उठता ।

(ख) हीरा मिल्स के पास शहर के दूसरे स्थानों में कोई भूमि नही है । इंदौर मालवा यूनाइटिड मिल्स की भूमि का कुछ भाग लगभग 7.7 एकड़ जो उसके परिसर के समीप ही था, भूतपूर्व प्रबन्धकों द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बेच दिया गया था । इस समय उक्त भूमि को अधिगृहीत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है ।

(ग) हीरा मिल्स के अधीन कोई और कारखाने नही चलाए जा रहे है । किन्तु इंदौर मालवा यूनाइटिड मिल्स के पास दो धुनाई कारखाने थे जिनमे से एक इंदौर में और दूसरा कन्नोड मे स्थापित था और इन्हें भी मिल के साथ हाथ में ले लिया गया था । इन दो कारखानों की भूमि कुल मिला कर 31.54 एकड़ है तथा इस भूमि का कोई भाग किसी राजनैतिक पार्टी के कब्जे में नहीं है ।

Setting up of Powerloom Board

9266. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Powerloom Board with a view to give encouragement and keeping in view its increasing popularity and the employment opportunities it provides;

(b) if so, the steps taken in this regard; and

(c) the percentage of cloth manufactured by cotton mills and powerlooms as also the number of workers engaged in each industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b) There is currently no proposal to set up a Powerloom Board.

(c) The Cotton Mills manufacture 46 21 per cent and Powerloom produce 32 87 per cent (cotton and art silk) of the cloth. About 11 lacs workers are employed by the Mill Sector and 8 67 lacs are employed in the Powerloom Sector.

Transfer of Hindi Teachers, Asstt. Directors under Hindi Teaching Scheme

9267. SHRI MADAN TIWARY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the policy regarding transfer of Hindi Teachers, Assistant Directors and Deputy Directors under the Hindi Teaching Scheme;

(b) the number of Hindi Teachers, Assistant Directors and Deputy Directors transferred during the period from 1973 to 1978;

(c) the category-wise number of employees transferred from Bombay to Delhi; and